दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 20 दिसम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 82

महत्वपूर्ण एवं खास

छह माह तक मनाली-लेह मार्ग बंद, बीआरओ नहीं हटाएगा बर्फ

कुल्लू (आरएनएस)। मनाली-लेह जाने वाले वर्यटकों के लिए एक बूरी खबर सामने आई है। रोहतांग दर्रे पर रिकॉर्ड 8 फीट बर्फबारी की वजह से मनाली-लेह मार्ग इस बार तीन हफ्ते पहले ही वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। भले ही यह मार्ग आधिकारिक तौर पर 15 नवंबर से मई महीने तक बंद कर दिया जाता है लेकिन 31 दिसंबर तक मौसम खुलने के दौरान सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) इसे लोगों की सुविधा के लिए बहाल करता रहा है। इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी की वजह से बीआरओ ने बर्फ न हटाने का फैसला लिया है। अब मई महीने तक इस मार्ग पर कोई भी वाहन नहीं चल सकेगा। रोहतांग टनल से आवाजाही 25 नवंबर से बंद है, जबकि रोहतांग दर्रा 19 नवंबर से बंद है। हालांकि, बीआरओ ने दर्रे से बर्फ हटाकर इसे बहाल कर दिया था, मगर एक हफ्ते तक रोहतांग के आसपास बर्फीला तूफान आने से यह फिर से बंद हो गया है।

जनसंख्या स्थिर रखने रोडमैप तैयार करेगा नीति आयोग

नईदिल्ली(आरएनएस)। नीति आयोग जनसंख्या स्थिर रखने के उपायों पर चर्चा तथा इसके लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए कल 20 दिसंबर को नयी दिल्ली में ''जनसंख्या स्थिरीकरण की सोच को साकार करने: किसी को पीछे नहीं छोड़ने'' विषय पर पॉपुलेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर एक सलाहकार सम्मेलन आयोजित करेगा। यह बैठक देश की जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मजबूत करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगी। सम्मेलन के सुझाव 15 अगस्त 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के किए गए आह्वान को साकार करने में मदद करेंगे। सुझावों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाने वाले मसौदे के परिवार नियोजन कार्यक्रमों में आने वाली कमियों को दूर करने में मददगार होने की संभावना है।

ढुलाई के अनुरूप डिब्बे डिजाइन करने हेतु रेल मंत्रालय का सम्मेलन

नईदिल्ली (आरएनएस)। नई तरह की वस्तुओं की ढुलाई के अनुरुप डिब्बे डिजाइन करने के लिए आज रेल मंत्रालय की ओर से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह इस तरह का तीसरा सम्मेलन था। इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल,इस्पात,सीमेंट,अनाजों और अन्य तरह की विशेष वस्तुओं की ढुलाई में आने वाली दिक्कतों से निबटने के अभिनव तरीके ईजाद करने तथा माल ढुलाई के क्षेत्र में भारतीय रेल के लिए बाजार संभावनाओं का पता लगाने के लिए रोडमैप तय करना था। यह रेलवे द्वारा प्रमुख साझेदारों के सहयोग से माल ढुलाई के क्षेत्र में आनी वाली दिक्कतों का व्यावहारिक समाधान तलाशने का एक प्रयास था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रेलवे बोर्ड के सदस्य राजेश अग्रवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश मे कुल माल ढुलाई का 45 प्रतिशत रेल से किया जाए। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई के लिए एक बार समर्पित गलियारा बन जाने से रेल के जरिए सामान लाने ले जाने की गतिविधियों में काफी तेजी आ जाएगी।

अमेरिका में सिख टैक्सी चालक पर हमला

न्यूयार्क। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के एक सिख टैक्सी चालक को उसके घर के सामने बेरहमी से पीटा गया। मीडिया खबरों में यह जानकारी दी गई है।एसएफगेट डॉट कॉम की खबर के अनुसार एक डाक वाहक और उबर चालक के रूप में काम करने वाले बलजीत सिंह सिद्धू पर रविवार को उस दौरान हमला किया गया जब वह कैलिफोर्निया के रिचमंड में हिलटॉप मॉल के निकट अपने घर के बाहर अपनी कार को खड़ा कर रहे थे। खबर के अनुसार जब वह अपनी कार पार्क कर रहे थे तो इसी दौरान एक आदमी उनकी टैक्सी के पास आया और उनसे लाइटर मांगा।

अब सीमा पर तैनात एएसबी जवानों को मिलेगी 100 दिनों की छुट्टी

» गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव पर कर रहा विचारः अमित शाह

नई दिल्ली (आरएनएस)। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों को जल्द 100 दिनों की छुट्टियां दी जाएंगी। इस संबंध में एक प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। नई दिल्ली में एसएसबी की 56 वीं वर्षगांठ परेड के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक-डेढ़ साल में हम ऐसी स्थिति ला देंगे कि एसएसबी का हर एक जवान जो सीमा की सुरक्षा करता है, वो साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सके, ऐसी व्यवस्था गृह मंत्रालय करने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एसएसबी के लिए गृह मंत्रालय ने ढेर सारी सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है। कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु को 57 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है।

नेपाल और भूटान सीमा से घुसपैठ की कोशिश

अमित शाह ने कहा कि जो लोग भारत में शांति देखना नहीं चाहते वह भारत में प्रवेश करने के लिए देश की नेपाल और भूटान से लगने वाली सीमा का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। 130 करोड़ लोग चौन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सीमा की सुरक्षा करने वाले जवान शत्रुतापूर्ण माहौल में भारत की रक्षा करते हैं।

एसएसबी का काम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एसएसबी ने अपने पहले अवतार में जो काम किया है, जब भी भारत की एकता और अखंडता का इतिहास लिखा जायेगा, वह उसमें स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा।

भारत-चीन युद्ध के बाद जब इसकी स्थापना हुई तो इसका काम था कि सीमावर्ती गांव व भारत के साथ जुड़ाव का सांस्कृतिक भाव जागृत करना और भारत के साथ इन गांवों को जोड़कर पूरे देश में सांस्कृतिक तारतम्य जोड़ना। एसएसबी ने अपना काम पूरी निष्ठा से किया है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां इसके जवान लगे, चाहे मित्र राष्ट्र की सीमाएं हों, कश्मीर हो, नक्सलवादी क्षेत्र हो, हर जगह उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। एसएसबी ने राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा के लिए बलिदान देने से अभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

हैदराबाद में सीएए विरोधी रैली में जा रहे प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

हैदराबाद (आरएनएस)। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हैदराबाद में एक रैली में भाग लेने जा रहे दर्जनों कार्यकर्ताओं और वामपंथी नेताओं को पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में ले लिया है। पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को शहर का दिल कहे जाने वाले एक्जीबिशन ग्राउंड्स में जाने के दौरान रोका।

वामपंथी दलों और कई मुस्लिम संगठनों ने एक्जीबिशन ग्राउंड्स से राज्य विधानसभा भवन तक रैली का आह्वान किया था। हालांकि रैली करने के लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। रैली में शामिल होने के लिए जा रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता व पूर्व सांसद अजीज पाशा भी गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे अजीज पाशा ने कहा, यह अन्यायपूर्ण है। यह लोकतंत्र है या पुलिस राज। उनका कहना है कि वह संविधान और वामपंथी दलों से जुड़े मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों ने बुर्का पहनी महिलाओं को भी रैली में जाने से रोका। इस रैली की योजना वास्तविक तौर पर ऐतिहासिक चारमीनार से एक्जीबिशन ग्राउंड्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन साउथ जॉन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी।

करतारपुर रेलवे स्टेशन पर सरयू-यमुना एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, 3 बोगियां जलकर खाक

» यात्री सुरक्षित

जालंधर (आरएनएस)। पंजाब के करतारपुर में रात को बड़ा हादसा होने से बच गया। करतारपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी सरयू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन में बुधवार रात अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसकी चपेट में 3 बोगियां आ गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित हैं।

फायर ब्रिगेड की 6 गाडियों ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक, यह ट्रेन रात करीब 10.30 बजे करतारपुर पहुंची तो एस-2 कोच से धुआं उठता दिखा।

यह आग देखते ही एस-1 और एस-3 कोच मे भी फैल गई। इस आग में एस-2 कोच तो पूरी तरह जलकर खाक हो गया, वहीं अन्य दो कोचों को भी काफी नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि जिस समय आग लगी उस वक्त ट्रेन में लोग सो रहे थे।

आग की सूचना पाते ही हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। रेलवे अधिकारियों ने वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ट्रेन में आग लगने की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही आग लगने के कारणों के बारे में बताया जा सकेगा। स्टेशन मास्टर जंग बहादुर ने बताया कि जिस समय आग लगी, उस समय ट्रेन के तीन कोच में 100 के करीब यात्री सवार थे। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है।

महिलाओं से अपराध में सजा देर से मिले तो जनता में आक्रोश बढ़ता हैः सुको

नई दिल्ली। निर्भया कांड में दोषियों को सजा देने में सात साल का इंतजार और हैदराबाद केस के बाद जनता में आक्रोश से सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता बढ़ गई है। महिला अपराधों से निपटने और दोषियों को समय से सजा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिस वाली बेंच ने सुओ मोटो रिट के जरिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों की खबर ली है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से निर्भया फंड का ब्योरा भी तलब किया है। इस स्वतः संज्ञान वाली रिट याचिका के जरिए कोर्ट ने कहा कि न्याय में देरी जनता के मन में अशांति, गुस्सा और अधीरता पैदा करती है. चीफजस्टिस बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस रिट के हवाले से ये भी कहा है कि न्याय प्रक्रिया की पेचीदगी की वजह से न्याय मिलने में देरी जनता के मन में अशांति, गुस्सा और आक्रोश पैदा करती है। कोर्ट ने कहा कि निर्भया केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद जनता की भावना को देखते हुए संसद ने कानून में भी बदलाव किया, लेकिन निर्भया केस आज तक अंतिम पडाव पर नहीं पहुंच पाया. जबकि ये अकेला ऐसा केस नहीं है। जस्टिस बोबडे ने कहा कि एजेंसिया लोगों के गुस्से को देखकर तेजी से काम करती हैं. महिलाओं से रेप के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बडा कदम उठाया है. चीफजस्टिस बोबडे ने देशभर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया।

केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस

चीफजस्टिस ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर कहा है कि मौजूदा कानून, सिस्टम और पुलिस कार्रवाई के तरीकों को सख्त और जवाबदेह करने की जरूरत है। इतना ही नहीं पीड़ितों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता में होना चाहिए। केंद्र सहित सभी राज्यों के लिए जारी नोटिस में चीफ जस्टिस ने कहा है कि 2017 में देशभर में 32559 रेप केस सामने आए जो कि बेहद चिंताजनक हैं।

सीजीएचएस सेवाओं का विस्तार 100 शहरों में किया जाएगाः डॉ. हर्षवर्धन

» विकासपुरी में सीजीएचएस डिस्पेंसरी समर्पित

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि सीजीएचएस सेवाओं का विस्तार अब 100 शहरों में किया जाएगा। डॉ. हर्षवर्धन ने पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा की उपस्थिति में विकासपुरी, नई दिल्ली में सीजीएचएस की एक नई डिस्पेंसरी का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में यह योजना 329 एलोपैथिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 86 आयुष केन्द्रों के जरिए 72 शहरों में चल रही है। इस सेवा का 12.09 लाख प्राथमिक कार्डधारक और 35.72 लाख लाभार्थी लाभ उठाते हैं, जिनमें से 17 लाख लाभार्थी दिल्ली/एनसीआर के 2.5 लाख से अधिक लाभार्थी 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं। करीब 58 प्रतिशत सीजीएचएस लाभार्थी एक वर्ष में कम से कम एक बार सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाते है।

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद 72 शहरों में सीजीएचएस तंदुरूस्ती केन्द्रों की संख्या पूर्व की संख्या 30 से बढ़ायी गई है, जिससे पता लगता है कि सरकार कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनकी तंदुरूस्ती के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। जल्दी ही सीजीएचएस का विस्तार इटानगर, कन्नूर और कोझीकोड़ शहरों में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में मंत्रालय विभिन्न साझेदारों को लाभार्थियों और अन्य से प्राप्त जानकारियों और सुझावों को काम में लाया है, ताकि सीजीएचएस केन्द्रों के जरिये स्वास्थ्य सेवाएं देने के काम में सुधार लाया जा सके। 80 वर्ष की आयु से अधिक लाभार्थियों के लिए सीजीएचएस केन्द्रों के डॉक्टर महीने में कम से कम एक बार उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते हैं/यदि 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हों, तो घर में जाकर देखते हैं।

उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता की झलक है कि एम्स की संख्या अब बढ़कर 21 हो गई हैं। इस समय 6 एम्स कार्य चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। ये मुख्यतः देश के आकांक्षापूर्ण जिलों में स्थापित किये जा रहे हैं, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें और उन्हें लंबी दूरी तय करके नहीं जाना पड़े।

डीआरडीओ ने पिनाक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया

चांदीपुर (आरएनएस)। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित पिनाक मिसाइल प्रणाली का गुरुवार को ओडिसा के चांदीपुर तट के निकट स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल उड़ान परीक्षण किया गया। पिनाक आर्टिलरी मिसाइल प्रणाली है, जो पूरी सतर्कता के साथ दुश्मन के इलाके में 75 किलोमीटर तक मार कर सकती है।

पिनाक एम.के.-2 रॉकेट को मिसाइल के रूप में सुधारा गया है, जिसमें नौसंचालन, नियंत्रण और दिशा-प्रणाली जोड़ी गई हैं, ताकि उसकी सटीकता और रेंज में इजाफा हो सके। मिसाइल की नौसंचालन प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नौसंचालन उपग्रह प्रणाली से भी मदद मिलती है।

इस मिशन ने रेंज, सटीकता और संचालन प्रणाली की सभी गतिविधियों को कामयाबी से पूरा किया। इसकी ट्रैकिंग टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग प्रणाली से की जाती है। मिसाइल प्रणाली को डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं ने विकसित किया है, जिनमें आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना (एआरडीईई), अनुसंधान केन्द्र इमारत (आरसीआई), रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल), फ्रूफ एवं प्रयोगात्मक संगठन (पीएक्सई) और उच्च उर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) शामिल हैं।

भारत और रूस की तीनों सेवाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'इंद्र-2019' समाप्त

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत और रूस की तीनों सेवाओं का दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'इंद्र-2019' गुरुवार को बबीना, पुणे और गोवा में पूरा हो गया। इस अभ्यास के अंतर्गत आतंकवादरोधी और उग्रवादरोधी संयुक्त प्रशिक्षण किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के नीतिगत आदेशों के अनुरूप था। इस दौरान आतंकवादरोधी अभियानों से जुड़े महत्वपूर्ण व्याख्यान, प्रदर्शन और ड्रिल के जरिए संयुक्त रूप से अभ्यास किया गया। दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा किया।

सैन्य अभ्यास का अंतिम दौर 19 दिसंबर को पूरा हुआ। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने विशेष संयुक्त आतंकवादरोधी अभियान का अभ्यास किया। इस अभ्यास को दोनों देशों की सेनाओं से जुड़े अधिकारियों और विशिष्टजनों ने देखा।

रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी और अभ्यास में हिस्सा लेने वाले दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अभ्यास का अवलोकन किया। रूसी पक्ष की तरफ से वहां के पूर्वी सैन्य जनपद के उप-कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई सेरुकोव भी उपस्थित थे। अभ्यास के समापन समारोह में दोनों देशों की सेनाएं शामिल रहीं।

इंद्र-2019 सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच मैत्री और सौहार्द बढ़ाने में बहुत सफल रहा है। इस अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूती प्रदान करने में बहुत सहायता मिली है।

सीतारमन ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने आगामी आम बजट 2020-21 के सम्बन्ध में विभिन्न ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आज नई दिल्ली में बजट पूर्व पांचवा विचार-विमर्श किया।

बैठक के दौरान ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रम और रोजगार से जुड़े मुद्दों के सम्बन्ध में अपने विचार और सुझाव साझा किए। बैठक में वर्तमान श्रम बल के कौशल विकास, नया हुनर सिखाने और अतिरिक्त हुनर देने के बारे में भी चर्चा की गई। इसके अलावा नौकरियों के सृजन की गुणवत्ता और कामगारों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के बारे में भी बातचीत की गई। केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर; वित्त सचिव राजीव कुमार; डीईए सचिव अतनु चक्रवर्ती; राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे; सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी; प्रमुख आर्थिक सलाहकार डॉ. के.वी. सुब्रह्मण्यम; श्रम और रोजगार मंत्रालय सचिव हीरालाल सामरिया; वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के महानिदेशक एच.श्रीनिवास और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने नौकरियां सृजित करने, श्रम से जुड़ी चिंताओं और रोजगार की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने कौशल विकास, नया हुनर सिखाने और अतिरिक्त हुनर देने के अलावा सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के बारे में अपनी चिंताएं बताई। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बेहतर परिणामों की आवश्यकता के अलावा नौकरियां सृजित करने की गुणवत्ता और कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।